भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4475
जिसका उत्तर 20 अगस्त, 2025 को दिया जाना है।
29 श्रावण, 1947 (शक)

लैपटॉप विनिर्माण इकाइयों की स्थापना

4475. श्री इटेला राजेंदरः
श्रीमती डी. के. अरुणाः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र/राज्य सरकारों ने राज्यों में, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक सिटी, हाई-टेक सिटी-हैदराबाद जैसे शहरों में लैपटॉप विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए किसी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि हाँ, तो ऐसे निवेशों का ब्यौरा क्या है;
(ख) ऐसे पार्कों में स्थापित/स्थापित होने वाली पुरानी/नई इकाइयों की संख्या कितनी है और चूंकि नई नीतियों, मजबूत अवसंरचना, अत्यधिक कुशल कार्यबल और सबसे बढ़कर तेज गति से व्यापार करने में आसानी के साथ यह भारत में विनिर्माण के लिए सबसे आकर्षक गंतव्य है, इन जिलों के आसपास के क्षेत्रों में लगभग कितने लोगों (लाखों में) के लिए रोजगार सृजन होने की सम्भावना है;
(ग) हमारे देश में ऐसे लैपटॉप की बिक्री से अब तक कितनी आय हुई/कितना लाभार्जन हुआ है; और
(घ) ऐसी इकाइयों को कितनी प्रोत्साहन राशि और क्या अन्य प्रोत्साहन दिए गए हैं और सरकारी/निजी कंपनियों द्वारा राज्यवार, विशेषकर तेलंगाना में, किए गए निवेश और अर्जित लाभ क्या हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरा है। इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि इस प्रकार देखी जा सकती है:

#	2014-15	2024-25	टिप्पणी
इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का उत्पादन (₹)	1.9 लाख करोड़	11.3 लाख करोड़	6 गुना वृद्धि
इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों का निर्यात	0.38 लाख करोड़	3.3 लाख करोड़	8 गुना वृद्धि
मोबाइल विनिर्माण इकाइयाँ	2 इकाइयाँ	300 इकाइयाँ	150 गुना वृद्धि
मोबाइल फोन का उत्पादन (₹)	0.18 लाख करोड़	5.5 लाख करोड़	28 गुना वृद्धि
मोबाइल फोन का निर्यात (₹)	0.01 लाख करोड़	2 लाख करोड़	127 गुना वृद्धि
आयातित मोबाइल फोन (कुल इकाइयों का %)	मांग का 75%	मांग का 0.02%	

सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं को बढ़ावा देने वाली साझा सुविधाओं के साथ-साथ विश्व स्तरीय अवसंरचना के निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए ईएमसी और संशोधित ईएमसी (ईएमसी 2.0) योजनाओं को लागू कर रही है। ईएमसी योजना के अंतर्गत, 15 राज्यों में 19 ग्रीनफील्ड ईएमसी और 3 सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्वीकृत किए गए हैं। ईएमसी 2.0 योजना के अंतर्गत, देश भर के 9 राज्यों में कुल 10 ईएमसी और 2 सीएफसी स्वीकृत किए गए हैं। तेलंगाना में, 3 ईएमसी और 1 सीएफसी को स्वीकृति दी गई है।

इसके अलावा, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आईटी हार्डवेयर मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए, आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई 2.0 योजना दिनांक 29.05.2023 को शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत लक्षित खंडों में (i) लैपटॉप (ii) टैबलेट (iii) ऑल-इन-वन पीसी (iv) सर्वर और (v) यूएसएफएफ (अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर) उपकरण शामिल हैं।

उद्योग के अनुमान के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में लगभग 25 लाख रोजगार (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष) सृजित हुए हैं।

रोजगार सृजन में सहायता करने वाली भारत सरकार की प्रशिक्षण/कौशल पहल:

- स्मार्ट लैब, नाइलिट कालीकट में 44,000 से अधिक इंजीनियरों को प्रशिक्षित किया गया।
- एआईसीटीई ने वीएलएसआई डिजाइन और आईसी विनिर्माण के लिए नया पाठ्यक्रम शुरू किया है।
- 350 से अधिक विश्वविद्यालयों और स्टार्टअप्स को ईडीए उपकरण प्रदान किए गए, जिससे 45,000 से अधिक छात्र लाभान्वित हुए।
- चिप डिज़ाइन सहायता: डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) योजना के अंतर्गत 22 स्टार्ट-अप्स को सहायता प्रदान की गई
- अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ, सिंगापुर, आईबीएम और पर्ड्यू विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन। एप्लाइड मैटेरियल्स और एलएएम रिसर्च जैसे उद्योग जगत के दिग्गजों ने भी अनुसंधान, सत्यापन और कार्यबल विकास केंद्र स्थापित किए हैं।

इसके अलावा, सरकार डिजिटल साक्षरता और आईटी कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को रोज़गार के अवसर प्रदान कर उन्हें सशक्त बना रही है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और नैसकॉम (एनएएसएससीओएम) का एक संयुक्त प्रयास, फ्यूचरस्किल्स प्राइम, भारत में डिजिटल प्रतिभा नेतृत्व के निर्माण हेतु उद्योग-आधारित, अत्याधुनिक पाठ्यक्रम प्रदान करके इस मिशन को गति प्रदान करता है। प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, आईओटी, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन, एआर/वीआर आदि में कौशल, पुनः कौशल और अपस्किलिंग।
- वास्तविक रोजगार आवश्यकताओं के अनुरूप उद्योग के परामर्श से पाठ्यक्रम विकसित किए जाते हैं
- अपनी योग्यता और आकांक्षाओं के अनुरूप कौशल प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पोर्टल का उपयोग कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है
- https://futureskillsprime.in/ पर ऑनलाइन उपलब्ध है

फ्यूचरस्किल्स प्राइम कार्यक्रम के अंतर्गत, अब तक 22.9 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं, जिनमें से 13.8 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों का नामांकन हो चुका है। इसके अलावा, 18,785 सरकारी अधिकारियों, 2,367 प्रशिक्षकों और 19,929 छात्रों (208 बूटकैंप के अंतर्गत) को सीडैक और नाइलिट केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है।

*****